कांग्रेस

आम आदमी के बढ़ते कदम
हर कदम पर भारत बुलंद

लोकसभा चुनाव 2009

घोषणा-पत्र

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मुख्य बिंदु

कांग्रेस क्यों?

एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी

- केंद्र में सरकार की स्थापना के लिए यह एक राष्ट्रीय चुनाव है और इस सरकार के पास समूचे भारत के शासन का दायित्व होगा
- कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसके पास अखिल भारतीय दृष्टि है और इसकी देशभर में मौजूदगी है

लगातार अच्छे प्रदर्शन का रिकॉर्ड

- कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड समग्र विकास और प्रगति को लेकर उसकी प्रतिबद्धता की कहानी कहता है
- कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2004 में जनता के समक्ष जो संकल्प लिए थे उन्हें पूरा करके दिखाया है और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा

एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ और जीत सकता है

- सिर्फ कांग्रेस पार्टी एकजुट एवं धर्मनिरपेक्ष भारत में विश्वास रखती है और इस दिशा में काम करती है
- सिर्फ एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत ही आतंकवाद का इस तरीके से मुकाबला कर सकता है जिससे हमारे समाज का धर्मनिरपेक्ष तानाबाना प्रभावित न हो

कमज़ोर वर्ग, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के साथ सभी भारतीयों के लिए दृष्टि

- हमारे नानाविध समाज के सभी वर्गों के लिए हमारे पास एक दृष्टि और कार्यक्रम हैं
- हमारे कार्यों में महिलाओं के लिए समानता, कमजोर तबके का सशक्तिकरण, किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण जैसे मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता साफ तौर पर झलकती है

एक ईमानदार, बुद्धिमान और ठोस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री

- डॉ. मनमोहन सिंह के रूप में हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें अनोखी योग्यताएं, अद्वितीय अनुभव, निष्कलंक छवि और निर्विवाद सत्यनिष्ठा है
- भारत के समक्ष उभरी नई चुनौतियों को देखते हुए अब उनकी बुद्धिमता, ज्ञान और विशेषज्ञता की पूर्व की तुलना में सबसे ज्यादा जरूरत है

कांग्रेस के लिए वोट, वोट सुरक्षा के लिए, हर भारतवासी के गौरव और समृद्धि के लिए

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड

वादे किए और निभाए

अच्छी शासन व्यवस्था

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- एक परिपूर्ण विधान, जो हर नागरिक को इस काबिल बनाता है कि वह सभी स्तरों पर बैठे सरकारी अधिकारियों से जवाबदेही और उत्तरदायित्व की मांग कर सके

गरीबों को रोजगार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए)

- रोजगार चाहने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिन का कानूनन गारंटीशुदा रोजगार मुहैया करवाता है जिससे इन परिवारों की आजीविका और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन सुनिश्चित हो सके
- इस योजना के अंतर्गत समूचे भारत में 9 करोड़ नागरिकों को रोजगार मिला

शहरी विकास

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनयूआरएम)

- गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे और आधारभूत सुविधाओं में निवेश करते हुए इस अभूतपूर्व कार्यक्रम ने कस्बों और शहरों का कायापलट कर दिया
- 42,000 करोड़ रु. लागत की परियोजना को स्वीकृति मिली और यह प्रगति पर है

स्वास्थ्य और शिक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

- प्राथमिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता और लोगों तक पहुंच के लिए नए सिरे से जोर
- लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 6.5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएसएचए या आशा) के रूप में मान्यता दी गई

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याह्न भोजन योजना

- एनडीए सरकार की तुलना में प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के लिए प्रावधान में पांच गुना बढ़ोतरी
- संपूर्ण भारत के 15 करोड़ बच्चों के लिए पका हुआ मध्याह्न भोजन सुनिश्चित किया

कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण

महिला अधिकार

- घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए एक नया कानून बनाया
- महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाने के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए

अजा/अजजा, ओबीसी और अल्पसंख्यक

- अजा/अजजा, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए वजीफे में भारी इजाफा
- अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के लिए भू-अधिकार
- आर्थिक मोर्चे पर रिकॉर्ड प्रदर्शन

भारत के लिए विकास का प्रक्षेपपथ

- यूपीए सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड 8.8 फीसदी की औसत आर्थिक विकास दर रही जबकि एनडीए सरकार के समय यह महज 5.8 फीसदी थी

सामाजिक क्षेत्र पर रिकॉर्ड व्यय

- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी

ग्रामीण विकास

भारत निर्माण

- ग्रामीण भारत के कायापलट का एक कार्यक्रम जिसके तहत सिंचाई, सभी ऋतुओं के लिए अनुकूल सड़कें, गरीबों के लिए आवास, पानी की उपलब्धता, बिजली और टेलीफोन नेटवर्क से सभी गांवों को जोड़ने जैसी सुविधाओं का विस्तार

किसानों को आर्थिक सुरक्षा

राष्ट्रीय कृषि ऋण माफी कार्यक्रम

- 65,000 करोड़ रु. के ऋणों की माफी से छोटे किसानों को बड़ी राहत

किसानों के लिए बेहतर सौदा

- किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और उपार्जन मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि
- किसानों के लिए उपलब्ध कर्ज में तीन गुना बढ़ोतरी और ब्याज दरों में कमी

राष्ट्रीय सुरक्षा

बेहतर उपकरणों से लैस पुख्ता सुरक्षा

- हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोष, शक्तियों और संसाधनों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी, आतंकवाद से मुकाबले के लिए अब ज्यादा कड़े कानून

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की स्थापना

- आतंकवाद संबंधी प्रकरणों की जांच और अभियोग के लिए एक नई विशेषज्ञ एजेंसी

जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा

- जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने में सफलता, राज्य विधानसभा चुनाव में जनता की रिकॉर्ड भागीदारी से इसकी पुष्टि

भारत की नई वैश्विक पहचान

सफल विदेश नीति

- हमारी अपनी शर्तों पर नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई देशों के साथ आण्विक समझौते
- हरेक वैश्विक मंच पर भारत के लिए सम्मानजनक स्थान हासिल किया

भविष्य की राह (2009-2014)

हमारी प्रस्तावित कार्यसूची के तत्व

हम देश के हरेक नागरिक के लिए अधिकतम संभव सुरक्षा की गारंटी देंगे

- आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करना सुनिश्चित करेंगे
- समूचे देश में विशेष बलों की स्थापना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी
- हमारे सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक मारक हथियारों, प्रौद्योगिकी और विश्लेषणात्मक उपकरणों से लैस करने की प्रक्रिया जारी रहेगी
- हम अपनी वीआइपी/वीवीआइपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे उच्चस्तरीय सुरक्षा बल राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारियों से विमुख न हों
- 2011 तक सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान-पत्र देना सुनिश्चित करेंगे

एनआरईजीए की सफलता को आधार मान कर हम इसे आगे बढ़ाएंगे

- हम एनआरईजीए के अंतर्गत कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी आधारित उपलब्धता 100 रु. प्रति दिन की वास्तविक मजदूरी पर सुनिश्चित करेंगे

एनआरईजीए की तर्ज पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करेंगे

- हम एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करेंगे जिससे सभी लोगों को पर्याप्त भोजन के अधिकार की गारंटी मिले, खासतौर पर समाज के सर्वाधिक संवेदनशील लोगों को
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हरेक परिवार को, कानूनन, प्रति माह 3 रु. प्रति किलो की दर से 25 किलोग्राम गेहूं या चावल हासिल करने की पात्रता होगी
- आवासविहीन लोगों और प्रवासियों के लिए शहरों में रियायती सामुदायिक रसोईघर स्थापित किए जाएंगे

हम सब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी देंगे

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) की सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा आग्रह के साथ क्रियान्वित करेंगे.
- यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले तीन वर्षों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला हरेक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई) के कवर के अंतर्गत आ जाए

हम सब के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाएंगे

- जरूरत के मुताबिक, बगैर किसी समर्थक जमानत के हम सभी छात्रों को मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी भी मान्य पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए वज़ीफा या शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाएंगे
- हम स्कूलों में छात्रों की महज भर्ती के बजाए नतीजों और सीखने के स्तरों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे
- अगले पांच वर्ष तक हरेक ब्लॉक में, हर वर्ष एक नया आदर्श विद्यालय जोड़ेंगे
- शिक्षकों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे और स्कूलों के भौतिक पर्यावरण में सुधार करेंगे
- हमारी सरकार की ओर से शुरू किए गए उच्च शिक्षा विस्तार कार्यक्रम का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे. इस विस्तार के तहत 8 नए आइआइटी, 7 नए आइआइएम, 5 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 30 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, 20 नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, और 375 नए महाविद्यालय शिक्षा से वंचित जिलों में स्थापित किए जाएंगे

एक राष्ट्रव्यापी कौशल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगे

- देश में मौजूद मानव संसाधन के समुचित उपयोग और युवाओं की रोजगार पाने की काबिलियत में इजाफा करने के लिए एक सघन कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में 30,000 करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा तथा कौशल का ज्यादा व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा

हम किसानों और उनके परिवारों की खुशहाली के लिए योजनाओं का विस्तार करेंगे

- देश के प्रत्येक छोटे और सीमांत कृषक को कम ब्याज दरों पर बैंक कर्ज की सुविधा देंगे और जो किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं, उन्हें ब्याज में राहत देंगे
- कृषि के विविधीकरण, कृषि उपज के प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए व्यवस्थित रूप से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसानों के दरवाजे पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करेंगे

- राष्ट्रीय पुनरुद्धार और पुनर्वास विधेयक, 2007 के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिसे हम भाजपा के रोड़े अटकाने की युक्तियों की वजह से पारित नहीं कर सके थे

हम समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को और ज्यादा प्रोत्साहन देंगे

- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सफलता के अगले कदम के रूप में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के लिए विधेयक पारित हो
- हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि देश में ग्रामीण महिलाओं की कम-से-कम आधी आबादी बैंकों से जुड़े स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के रूप में नामांकित हों
- एक समान अवसर आयोग गठित करेंगे
- असंगठित क्षेत्र के पेशों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करेंगे और विकलांगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेंगे
- दलित और आदिवासी समुदायों के लड़के-लड़कियों के लिए सभी स्तरों–प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय–पर निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे
- निजी क्षेत्र में अजा/अजजा के लिए सकारात्मक कामकाजी नीतियों का अनुसरण करेंगे
- हर साल कम-से-कम 1 लाख अजा/अजजा छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग शुल्क का भुगतान करेंगे

हम बच्चों की विशिष्ट जरूरतों, खासकर लड़कियों पर विशेष ध्यान देंगे

- 2006 में स्थापित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानूनी गारंटी के तहत बच्चों के हितों का संरक्षण जारी रखेंगे
- हम मार्च, 2012 तक एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आइसीडीएस) का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करेंगे और हरेक बस्ती में एक आंगनवाड़ी उपलब्ध करवाएंगे
- प्रतिकूल लिंगानुपात को सुधारने के लिए हम बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाओं की पेशकश करते हुए उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे
- जिन जिलों में लिंगानुपात प्रतिकूल है वहां बालिकाओं को नकद लाभ देंगे. बालिकाएं जैसे-जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा पूरी करेंगी, उनके खाते में राशि जमा कर दी जाएगी

तीन वर्ष में हम गांवों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क में जोड़ेंगे

- तीन वर्ष के भीतर प्रत्येक गांव को हम ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ेंगे. इससे हम ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के ऐसे नए

अवसरों का सृजन कर सकेंगे जो कृषि आधारित न हों, इस प्रकार राजीव गांधी का ख्वाब–ग्रामीण कायापलट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल–बहुत अच्छी तरह पूर्ण हो सकेगा

हम छोटे उद्यमियों और लघु तथा मझले उद्यमों (एसएमईज़) पर विशेष ध्यान देंगे

- एसएमईज़ और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अधिक मात्रा में कोलेटरल-फ्री क्रेडिट, अनावश्यक कानूनी-कागजी कार्रवाई से राहत और इंस्पेक्टरों के चंगुल से आजाद करते हुए एक 'नया मौका' दिया जाएगा
- छोटे और मझले उद्यमों के विकास के लिए एक क्लस्टर (समूह) आधारित रास्ता अपनाया जाएगा, अधिकांशतः छोटे और मझले कस्बों में मौजूद इन उद्यमों को वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी, विपणन सहयोग और बुनियादी ढांचा मुहैया करवाया जाएगा

हम उच्च राजकोषीय विवेक और निम्न मुद्रास्फीति के साथ उच्च आर्थिक विकास दर के पथ पर बढ़ना जारी रखेंगे

- कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा अर्जित आर्थिक विकास दर को बरकरार रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे यूपीए सरकार के पहले चार वर्षों में विकास दर प्रति वर्ष 9 फीसदी रही जो भारत के इतिहास में पहली बार अर्जित की गई है
- विकास के उन पहलुओं पर जोर देना जारी रखेंगे जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लाभकर अवसरों का सृजन करते हैं
- निम्न महंगाई दर के साथ विकास की उच्च दर बरकरार रखेंगे, विशेष रूप से आवश्यक कृषि और औद्योगिक माल की कीमतों को नियंत्रित रखेंगे
- राजकोषीय जवाबदेही के मार्ग पर चलते रहेंगे ताकि केंद्र सरकार जरूरी सामाजिक और भौतिक ढांचागत सुविधाओं पर निवेश में वृद्धि क्रम लगातार जारी रख सके
- सब्सिडियों को निशाना बनाएंगे ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि इनका लाभ हमारे समाज के वास्तविक जरूरतमंदों और कमजोर वर्ग के लोगों को मिल सके

- यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भारत के लोगों को भागीदारी मिले
- विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दें जिसने पिछले कुछ वर्षों में पुनरुद्धार देखा है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों में
- निजी क्षेत्र की कंपनियों में सर्वोच्च स्तर का कंपनी सुशासन सुनिश्चित करेंगे. छोटे शेयरधारकों और निवेशकों की विशेष रूप से रक्षा करेंगे

हम 1 अप्रैल, 2010 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) शुरू करेंगे

- वैट के सफल क्रियान्वयन के बाद अब अगला निर्णायक कदम वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना होगा. एक बार जीएसटी क्रियान्वित हो जाएगा तो फिर केंद्रीय और राज्य स्तर के सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे

वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि हट जाएंगे और इससे आम आदमी को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी
- जीएसटी हमारे किसानों, कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक अखंड राष्ट्रीय साझा बाजार का निर्माण करेगा और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि पंचायतों और नगर-पालिकाओं के वित्त को मजबूती प्रदान की जा सकेगी

हम शहरी शासन व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करेंगे

- शहरी प्रशासन का एक नया मॉडल बनाया जाएगा जोकि वित्तीय रूप से व्यवहार्य स्व-सरकार संस्थान के रूप में होगा
- शहरी क्षेत्रों को और अधिक रहने योग्य बनाने के लिए बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका फोकस सस्ते सामाजिक आवास और सेनिटेशन की सुविधा होगी

हम शासन में शामिल करने के लिए युवाओं को नए अवसर देंगे

- हम युवाओं को सशक्त बनाने के अपने वादे पर कायम रहेंगे. एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी पहल राजीव गांधी ने मताधिकार की आयु 18 साल और स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करके की थी

- हम एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड को शुरू करेंगे जोकि 18-23 वर्ष की आयु के युवक-युवतियों को दो साल के लिए मजबूत राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों से जुड़ने में सक्षम बनाएगी
- सरकार के विभिन्न अंगों में युवाओं को शामिल करने की पहल की जाएगी. इसके तहत शुरुआत में, 35 साल से कम उम्र के स्त्री-पुरुषों के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएंगी

हम न्यायिक सुधार आगे बढ़ाएंगे ताकि न्याय में देरी न हो

- पिछले साल संसद द्वारा पारित ग्राम न्यायालय कानून के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा
- ग्रामीण इलाकों की मध्यवर्ती पंचायतों और मोबाइल अदालतों के मुख्यालयों में स्थित ग्राम न्यायालय आम आदमी के लिए त्वरित, वहन करने योग्य और ठोस न्याय लाएंगे

हम अपने देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे

- यह सुनिश्चित कराना कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से देश हर साल 12,000-15,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि करे
- यह सुनिश्चित कराना कि ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण हानि में कमी को उच्च प्राथमिकता मिले
- घरेलू और विदेशी प्रौद्योगिकी, दोनों ही माध्यमों से परमाणु ऊर्जा के हिस्से में इजाफा करना, जोकि अब हमारी सरकार द्वारा नागरिक परमाणु समझौते के बाद संभव नजर आता है

हम अपनी विरासत के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए और कदम उठाएंगे

- वैधानिक राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग का गठन अपनी बहुलतावादी संस्कृति और विरासत की नींव को और अधिक मजबूती देने के लिए यह अहम जरिया होगा

हम विकास में प्रवासी भारतीयों को शामिल करने के प्रयास तेज करेंगे

- हम देश की तरक्की में प्रवासी भारतीयों के योगदान को अधिक से अधिक करने के लिए मई 2004 में बनाए गए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की सफल गतिविधियों को जारी रखना सुनिश्चित कराएंगे
- चार नए विश्व-विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जिनमें पीआइओ/एनआरआई छात्रों के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी

अपील

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 125 सालों से हमारे देश के जन जीवन में मुख्य बिंदु रही है
- इसने भारत की विचारधाराओं को पिरोने का काम जिस तरह किया है वैसा किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया
- अपने पूरे इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकताएं, नीतियां और कार्यक्रम आर्थिक रूप से समृद्ध, न्याय से परिपूर्ण समाज, राजनैतिक रूप से एकीकृत और सांस्कृतिक सौहाद्र से परिपूर्ण भारत के निर्माण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई और क्रियान्वित की गई हैं
- मूल सिद्धांतों पर अडिग रहकर कभी भी नई और उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार
- हमारे देश के लोगों के पास एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भरोसा जताने का समय है
- अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनवरत प्रयास का ही नतीजा है
- पिछले छह दशकों में काफी कुछ हासिल किया जा चुका है
- लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की जनता के समक्ष पूरी विनम्रता, अपनी उपलब्धियों पर गर्व के साथ आती है लेकिन हमेशा ही एक राष्ट्र के तौर पर इंतजार कर रहे कार्यों को लेकर भी सजग रहती है
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की जनता से अपील करती है कि वह इसके योगदान, इसके दृढ़ निश्चयों, इसकी चिंताओं और इसके चार्टर के लिए पार्टी को वोट करें
- इस घोषणापत्र के जरिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दृढ़ निश्चय, प्रतिबद्धता, क्षमता और जुनून पर आधारित सामाजिक-आर्थिक बदलाव के संकल्प को नए सिरे से दोहराया है
- इस घोषणापत्र के जरिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खुद को सेवा की नीतियों और आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य की नींव को मजबूत करने वाली राजनीति के लिए पुनः समर्पित किया है
- इस घोषणापत्र के जरिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की जनता से अपने वादों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने का वचन दिया है
- भारत के विचार के लिए वोटः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट
- विविधता में एकता के लिए वोटः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट
- सांप्रदायिक सौहाद्रता के साथ आर्थिक विकास के लिए वोटः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट
- सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि के लिए वोटः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट
- सुरक्षा, स्थिरता, निरंतरता और अखंडता के लिए वोटः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट
- कांग्रेस को वोट यानी आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट

कांग्रेस

आम आदमी के बढ़ते कदम
हर कदम पर भारत बुलंद

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी

संपूर्ण घोषणा पत्र के लिए देखें: http://www.aicc.org.in/manifesto